शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार
मध्यप्रदेश

मप्र में कोरोना से मृत कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति

1 मार्च के बाद कोरोना से मरने वाले आएंगे इस दायरे में

भोपाल | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। पहली 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' और दूसरी विशेष अनुग्रह योजना। पहली योजना के तहत कर्मचारी के परिवार के पात्र दावेदार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। दूसरी योजना के तहत उन्हें 5 लाख रु. की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के 4.52 लाख नियमित कर्मचारियों के अलावा 1.75 लाख अध्यापक संवर्ग, 25 हजार पंचायत सचिव, 80 हजार नगरीय निकाय, 65 हजार निगम मंडलों के कर्मचारी, 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 80 हजार एएनएम और आशा कार्यकर्ता एवं 1.50 लाख पंचायतों में कार्यरत कोटवार को मिलेगा।

कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना

इसमें नियमित कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदाकर्मी के परिवार को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसका फायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को भी मिलेगा। आशा कार्यकर्ताओं के लिए जल्दी ही योजना बनेगी। अनुकंपा नियुक्ति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी। कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत लाभ ले चुके परिवार को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

विशेष अनुग्रह योजना... इसमें मृत कर्मचारी के परिवार में से पात्र दावेदार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी, इस तारीख के बाद कोरोना से मृतकों के परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें यह भी अहम होगा कि 1 मार्च के बाद जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनकी 60 दिन के भीतर मौत हुई है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

कोरोना से मौत पर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी और ₹ 5 लाख देगी सरकार

कर्मचारियों के परिवारों के लिए सीएम ने की योजना की घोषणा

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऐसी कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जहां काम करते हमारे कई कर्मचारी भाई-बहन हमसे बिछड़ गए। उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है। इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना तथा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। यह योजना जल्द शुरू की जाएगी।

कई फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोविड से जान गई

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से कई फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौत हो चुकी है। वायरस की चपेट में आकर कई डॉक्टर, नर्स और पुलिस जवान जान गंवा चुके हैं। योजनाओं के तहत कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी देने और उनके आश्रितों के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इन्हें मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

सभी नियमित, स्थाई कर्मचारी, कार्यभारित व आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक के परिजनों के आश्रितों में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार भी इसमें शामिल होंगे।

अब तक इतनी मौतें

■ शिक्षक, प्राचार्य	366
■ फॉरेस्ट कर्मचारी	122
■ बिजली कर्मचारी	35
■ पुलिस कर्मी	88
■ राज्य मंत्रालय	148

दो जिलों में 215 बच्चे अनाथ

कोरोना के कारण जिन बच्चों के मां-बाप का निधन हो गया, सरकार ऐसे बच्चों की सूची बनवा रही है। ताकि इन्हें 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन व अन्य सुविधाएं दी जा सकें। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि धार जिले में 125 तथा अलीराजपुर में 90 ऐसे अनाथ बच्चे मिले हैं।

बड़ा फैसला: शिवराज सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में लगे कर्मचारियों के लिए दो नई योजनाएं लांच की

कोरोना से मृत कर्मियों के परिवार में से एक को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख रुपए की सहायता भी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए शिवराज सरकार ने सोमवार को एक और बड़ा फैसला लिया। ऐसे शासकीय, कार्यभारित व आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैवेभो, तदर्थ व संविदा कर्मियों, आउटसोर्स, कलेक्टर दर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए व उसी तरह की संविदा नियुक्ति देगी, जिस पद पर वे शासकीय कर्मी कार्यरत थे। ऐसे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना व मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लांच की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के संकट काल में हमारे कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काम करते हुए हमारे कई कर्मचारी भाई-बहन कोविड-19 के दौरान हमसे बिछुड़ गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है।

खास बातें

- अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही
- प्रधानमंत्री मोदी ने मप्र को ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार में हर संभव मदद का आश्वासन दिया

क्या है यह योजनाएं?

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना

इसमें समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के तहत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

इन्हें भी मिलेगा इसका लाभ?

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संकट की स्थिति में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का संबल बनेगी। इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, वाम कोटवार इत्यादि कर्मी भी सम्मिलित होंगे। अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है ताकि इन परिवारों के जो आश्रित भाई-बहन हैं, उन्हें राहत मिल सके और उनकी आजीविका चलती रहे।

अब ज्यादा दूर नहीं कोरोना को किल करना

मुख्यमंत्री की निरंतर मॉनिटरिंग, सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण की स्थिति में आता जा रहा है। किल कोरोना अभियान को गति दी गई है। गांव-गांव में अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रवक्ता, भाजपा सरकार

◆ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की चर्चा

बताया-हमने काफी हद तक कोरोना कंट्रोल कर लिया

चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर मप्र में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मप्र में स्थिति अब नियंत्रण में है। मप्र में पॉजिटिव केस 5921 आए हैं। जबकि कुल 11,513 लोग डिस्चार्ज हुए। मप्र की सोमवार की रिकवरी रेट 87 फीसदी है। पॉजिटिव रेट महज 9 फीसदी रह गई है। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन और रेमडेसीविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार और उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री को किल कोरोना अभियान और वैक्सीनेशन की जानकारी भी दी।

कोरोना से निधन पर कर्मचारियों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण की वजह से बेसहारा हुए बच्चों को पांच हजार रुपये पेंशन, निशुल्क राशन और शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के लिए दो योजनाएं लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कोरोना से मृत कर्मचारियों के स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं पांच लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि भी परिवार के आश्रितों को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कर्मचारी शासन का अभिन्न अंग हैं। कोरोना महामारी के बीच वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि कोई घर से न निकले, अपने आपको सुरक्षित रखें। तब कर्मचारी मैदानी स्तर पर जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। व्यवस्थाएं करने में लगे हैं। राहत के कामों में जुटे हैं। इस दौरान कई कर्मचारी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवारों की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है।

इसके मद्देनजर दो योजनाएं बनाने का फैसला किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा योजना रहेगी। इसमें सभी नियमित, स्थायीकर्मी, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी,

राहत

- **पात्र दावेदारों को एकमुश्त पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी**
- **मुख्यमंत्री ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए दो योजनाएं की लागू**

सीएम शिवराज सिंह

तदर्थ, संविदा व क्लेक्टर दर पर काम करने वालों के आश्रितों को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही इन्हीं कर्मचारियों के पात्र दावेदारों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में यह राशि परिवार का संबल बनेगी।

इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम कोटवार सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए अलग से अनुकंपा योजना बनाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी संगठन अनुकंपा नियुक्ति और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता की मांग उठा रहे थे।

पीएम से बोले सीएम- प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, नए मामलों में तेजी से आ रही कमी

भोपाल(नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। नए प्रकरणों की संख्या तेजी के साथ घट रही है। सोमवार को 5,921 नए पॉजिटिव प्रकरण आए और स्वस्थ होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या 11,513 रही है। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 87 फीसदहै और संक्रमण दर नौ प्रतिशत है। संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा में दी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार माना। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर तक संकट प्रबंधन समूह बनाए हैं। पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी खोले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। इसके निशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि ब्लैक फंगस व कोरोना बीमारी को रोकने में मध्य प्रदेश को केंद्र हरसंभव सहायता करेगा।

निजी स्कूलों के दसवीं के छात्रों का रिजल्ट तीन साल के रिकॉर्ड से तैयार करने का मामला

प्राचार्य बोले-बोर्ड के इस फरमान से होशियार और मेहनत करने वाले बच्चों को होगा नुकसान

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893232137

माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) के द्वारा प्रायवेट स्कूलों के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का वार्षिक रिजल्ट तैयार करने का जो फंडा दिया गया है, उसके अनुसार मूल्यांकन के दौरान स्कूल के तीन साल के रिजल्ट से स्टूडेंट्स का भविष्य तय किया जाएगा।

ऐसे में बोर्ड का निर्णय न तो प्राइवेट स्कूल संचालकों के गले उतर रहा है और न ही सरकारी स्कूल प्राचार्यों की समझ में ही आ रहा है। उनका मानना है कि सरकार के इस निर्णय और बोर्ड की इस व्यवस्था से दसवीं के होशियार और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान होगा।

वहीं, स्कूल संचालकों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर रिजल्ट तैयार करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में अधिकतर स्कूल ही नहीं आए हैं। ऐसे में बच्चों के टेस्ट और अन्य परीक्षा का रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। ऐसे में पूरी जानकारी 30 मई तक भेजना संभव नहीं है।

उत्तर पुस्तिकाएं पैरेंट्स को दे दीं, अब वापस कैसे बुलाएं

बोर्ड ने 10वीं के मूल्यांकन का जो पैटर्न बनाया है, उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। जैसे कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण स्कूल बहुत कम लगे हैं। स्कूल में कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। कई स्कूलों में टेस्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ स्कूलों में टेस्ट, प्री बोर्ड, छमाही परीक्षाएं हुई भी हैं। परंतु उनकी उत्तर पुस्तिकाएं तभी पीटीएम के माध्यम से पैरेंट्स को दे दी गई हैं। अब पेरेंट्स स्कूल नहीं आ पाएंगे। यदि इस वर्ष के सभी बच्चों ने प्री बोर्ड या टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो उस एवरेज को कम करने के लिए किस विद्यार्थी के नंबर काटें, यह बड़ी समस्या है।

क्या कहते हैं स्कूल संचालक

अधिकतर बच्चों के टेस्ट हुए नहीं, कैसे बनाएं रिजल्ट

अधिकतर बच्चों के टेस्ट आयोजित नहीं हुए हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग कह रहा है कि टेस्ट के आधार पर रिजल्ट तैयार करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

-अजीत सिंह, अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मप

पैटर्न जटिल है, पढ़ने वाले बच्चों के प्रतिशत बिगड़ेंगे

बोर्ड के मूल्यांकन का पैटर्न जटिल है। कई पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत बिगड़ेंगे। हम शीघ्र ही शिक्षा मंत्री और मंडल, बोर्ड को पत्र में सुझाव भेजेंगे। इस मूल्यांकन पद्धति का विरोध करते हैं।

-दीपक सिंह राजपूत, संस्थापक, सोसायटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स

क्या कहते हैं शिक्षक संगठन

पैटर्न से शिक्षकों व प्राचार्यों के समक्ष कई समस्याएं

इस निर्णय के बाद पढ़ने वाले बच्चों की मेहनत बेकार हुई है और वह कहीं न कहीं इस पैटर्न के कारण तनाव में आ गए हैं। कोरोना महासंक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश सरकार का निर्णय तो बेहतर है, लेकिन अब इस निर्णय से शिक्षकों, प्राचार्यों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्योंकि, पूरे साल भर बच्चों से बेहतर तरीके से संपर्क नहीं हो पाया है।

-राजीव शर्मा, प्रांतीय सचिव, मप्र शिक्षक संघ

पैटर्न से बच्चों का नुकसान नहीं, परीक्षा का ऑप्शन भी

10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर मूल्यांकन का पैटर्न विशेषज्ञों के विचार-विमर्श के बाद तय किया गया है। दसवी कक्षा के बच्चों का रिजल्ट उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तीन साल की पाबंदी लगाना भी जरूरी था, अन्यथा मनमाने नंबर दे दिए जाते। इसके बाद भी असंतुष्ट बच्चों के लिए एग्जाम का भी आप्शन खुला हुआ है।

-इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा

10वीं की वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के ये हैं मापदंड

- 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा निरस्त की गई है।
- अर्द्धवार्षिक परीक्षा अथवा प्री-बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों से रिजल्ट बनेगा।
- उक्त तीनों प्रकार के मूल्यांकन के 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाएगी।
- सभी स्कूल ओएमआर शीट विषयवार भरकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास भेजेंगे।
- 10वीं के बच्चों की विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।
- सभी स्कूल अर्द्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं सीलबंद लिफाफे में एकत्र करके संबंधित स्कूल परिसर में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें मंडल को देंगे।
- उक्त सभी मूल्यांकन पद्धति को पूरा करने में स्कूल इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्कूल के तीन साल के रिजल्ट के औसत प्रतिशत से वर्तमान रिजल्ट 2 या 3 प्रतिशत से अधिक न हो।

कर्मचारी लगातार बताते रहे मैदानी दर्द, अब सरकार ने निभाया फर्ज

कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग करने पर मुख्यमंत्री ने लिया ऐतिहासिक फैसला

कोरोना में दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा देकर पालन करेगी सरकार

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ते हुए दिवंगत हो रहे कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों का अब सरकार पालन पोषण करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुविधाओं को लेकर उठती लगातार मांगों पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सीएम द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में काम करते संविदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे छोटे कर्मचारियों के मरणोपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि महामारी के दौर में अनेक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई। जहां काम करते.करते हमारे कई कर्मचारी भाई-बहन इस कोविड-19 के दौरान हमसे बिछड़ गए। वे इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवारों की देखभाल करना चिंता करना हमारी जवाबदारी है। इसलिए राज्य शासन ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री को विड.19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के अलावा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थाई कर्मी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक इन सबके परिवारों को आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी। चाहे किसी भी श्रेणी का कर्मचारी हो। उसके दिवंगत होने पर पात्र दावेदार को 5 लाख की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी। बताना होगा कि कोरोना में ड्यूटी करते समय आ रही अनेक समस्याओं को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठन लगातार सुविधाओं की मांग करते रहे हैं। इसके बाद सरकार ने यह सुविधा देने का फैसला किया है।

संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री हर वर्ग के प्रति चिंतित: शिव चौबे

मुख्यमंत्री के सलाहकार शिव चौबे का कहना है कि महामारी के इस दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर कर्मचारी संवर्ग के प्रति चिंतित है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित मे ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा संकट की इस घड़ी में अनुग्रह राशि देने का जो फैसला किया गया है। वह राशि उनके परिवारों का सम्बल बनेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ताए कोटवाल इत्यादि सभी कर्मी सम्मिलित होगे। अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओ के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है।

अनेक कर्मचारी संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के फैसले को सराहा गया

लगातार मांग करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस फैसले से कर्मचारी जगत ने बड़ी राहत की सांस ली है। स्वर्गवासी कोरोना योद्धा कर्मचारियों के परिवार जनों के लिए राहत भरी घोषणा की कर्मचारी वर्ग में विशेष रूप से सराहना की गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार शिव चौबे पूर्व कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा राजपत्रित अधिकारी संघ के डीके यादव मंत्रालय कर्मचारी संघ के सुधीर नायक निगम मंडल कर्मचारी महासंघ के अजय श्रीवास्तव नीलू शिक्षक संघ के छत्र वीर सिंह भूपेंद्र सिंह भरत पटेल जगदीश यादव मनोहर गिरी राजेंद्र शर्मा बालमुकुंद पाटीदार आईटीआई आईटीआई अनिल शर्मा छत्रवीर सिंह लघु वेतन कर्मचारी संघ के महेंद्र शर्मा फार्मासिस्ट संघ के राजेंद्र नायर, सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष हिंदी कुंवर बीएस चौहान अध्यापक संविदा शिक्षक महासंघ के प्रेम प्रकाश पंड्या राज कर्मचारी संघ हेमंत कुमार श्रीवास्तव एवं मुरारी लाल सोनी स्थाई कर्मचारी संघ के शारदा सिंह परिहार स्टेनोग्राफर संघ के अध्यक्ष एमएस मेवाड़ वाहन चालक संघ से साबिर खान, उदित कुमार भदोरिया अध्यक्ष जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ आदि ने मुख्यमंत्री का आभार माना है।

यूजी-पीजी की परीक्षाएं जून-जुलाई में

कॉलेजों में नवंबर के बाद तक जारी रह सकती है प्रवेश प्रक्रिया

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

कोरोना की वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाओं पर भी सीधा असर पड़ा है। अब स्नातक स्तर की परीक्षा जून और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। परीक्षाएं देर से होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब तक प्रवेश प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू नहीं हुई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की दलील है कि 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद ही स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित होने के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू होंगे। स्नातक परीक्षाओं के परिणाम जुलाई में घोषित किए जाएंगे। देर तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने की वजह से छात्रों को भी नुकसान होता है। उन्हें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाता। सालभर का कोर्स चार माह में पूरा करना होता है। अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होना चाहिए। लेकिन इस बार कोरोना की स्थितियों के वजह से यह नवंबर तक जारी रह सकती है।

उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी डॉ. धीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि अभी पूरा फोकस परीक्षाओं पर है। अगले महीने से परीक्षाएं होना है। इसके बाद 12वीं का जब परिणाम आएगा उसके बाद से प्रवेश शुरू होंगे। अगर स्थिति सामान्य रही तो जुलाई से प्रक्रिया शुरू होना चाहिए।

विवि की परीक्षाएं जून में, पंद्रह दिन बाद जारी करेंगे नतीजे

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना की वजह से पिछड़ी परीक्षाओं और परिणाम की व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों ने जून में परीक्षाएं करवाने पर जोर दिया है, ताकि नौकरी पा चुके विद्यार्थी जुलाई में अपनी-अपनी जाव ज्वाइन कर सकें। यहां तक कि अगस्त से नया सत्र शुरू किया जा सकेगा। मामले में विभागाध्यक्षों ने परीक्षा के पंद्रह दिन के भीतर नतीजे जारी करने पर सहमति जताई है। विभाग अगले कुछ दिनों में प्रश्न पत्र वनाना शुरू करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके आधार पर ही विश्वविद्यालय ने भी अपने विभागों की परीक्षा को लेकर रूपरेखा वनाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून दूसरे सप्ताह में परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। कुलपति डा. रेणु जैन ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग के रिजल्ट जल्द निकालने को कहा है। विभागाध्यक्षों ने इसके लिए 10 जुलाई तक रिजल्ट देने को कहा है। अव विश्वविद्यालय को लाकडाउन खुलने का इंतजार है। इससे जल्द ही परीक्षा की तारीख घोपित की जा सकेगी। इससे पहले विभाग को ओपन वुक पद्धति से प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। इससे विश्वविद्यालय के विभागों में दूसरे-चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करवानी है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है परीक्षा के वाद मूल्यांकन कर रिजल्ट देंगे।

कवायद

- **कोरोना के कारण पिछड़े सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश**
- **कुलपति की पहल पर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों ने जताई सहमति**

शाहजहांपुर के शिक्षक ने स्वावलंबन के मंत्र से विकसित किया इम्युनिटी तंत्र

नरेंद्र यादव ● शाहजहांपुर

मुश्किल वक्त में मजबूत सोच नए रास्ते बनाती है। ऐसा ही शिक्षक शरद कुमार सिंह ने भी किया। पिछले साल लाकडाउन में उन्होंने ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार का जरिया दिया और इम्युनिटी बढ़ाने का संसाधन भी। पहले खुद मधुमक्खी पालन शुरू किया, इसके बाद ग्रामीणों को साथ ले लिया। उनके इस प्रयास से गांव में प्रति माह 110 से 130 किलो शहद का उत्पादन हो रहा है। कोरोना काल में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए इसकी खूब मांग हो रही। ग्रामीण सतर्क हैं, इसीलिए गांव में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। शाहजहांपुर में सिधौली के प्राथमिक स्कूल, कठवा में 2018 से सहायक अध्यापक शरद कुमार सिंह ने पारिस्थितिकी व पर्यावरण में परास्नातक की पढ़ाई की। मधुमक्खी व रेशमकीट का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लिया था।

पिछले साल लाकडाउन में स्कूल बंद हुए तो उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल शुरू किया। देहरादून से दो बाक्स मंगवाकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। 10 हजार रुपये लागत में हर महीने करीब पांच हजार रुपये का शहद मिलने लगा।

विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन आज

भोपाल। कोरोना संक्रमण और उसके बाद भी हताश और उपेक्षा झेल रहे लोगों में भरोसा, मदद और समर्थन के लिए जागरूकता हेतु रचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 'माइंडफुल थॉट्स' नामक इस कार्यशाला में कोविड मुद्दों को समझ कर जागरूकता के लिए आर्टवर्क तैयार किए जाएंगे। इसमें 11वीं, 12वीं कक्षा के कलाकार बच्चे और कला शिक्षक भाग ले सकते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक अर्चना शर्मा और युवा इलस्ट्रेटर-डिजाइनर सुश्रुत सरकार मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में पोस्टर बनाए जाएंगे। मोबाइल नंबर 9926343930 पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वर्कशॉप 18 मई को दोपहर 2.30 बजे से गूगल मीट पर होगी। -(नप्र)

बच्चों ने ऑनलाइन सीखी वीडियो बनाने की तकनीक

ऑनलाइन क्लास में वीडियो बनाने के गुर सीखते बच्चे। ● **सौजन्य**

भोपाल। जवाहर बाल भवन के नाट्य प्रभाग के अनुदेशक एवं वरिष्ठ निर्देशक केजी त्रिवेदी ने सोमवार को बच्चों को ऑनलाइन क्लास में वीडियो बनाने की तकनीक सिखाई। उन्होंने विषय का चुनाव, कैमरे का एंगल, लाइट और साउंड की व्यवस्था कम से कम साधनों में करने का प्रशिक्षण दिया। श्री त्रिवेदी ने बच्चों की एक्टिंग एवं वीडियो बनाने संबंधी जिज्ञासा का समाधान भी किया। इस प्रशिक्षण में भोपाल सहित अन्य जिलों से भी बच्चों ने भाग लिया। भोपाल से काव्य पुरोहित, कबीर, विनीता, लक्ष्य, विभोर, प्रांजल, भूपेश, मोहित उपस्थित रहे। -(नरि)

स्पष्ट नीति ही नहीं : कोविड-19 को अब तक भी प्राकृतिक आपदा नहीं माना, इसलिए सरकारी मदद को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ

सरकार की नजर में कोरोना वॉरियर कौन...? स्वास्थ्य, राजस्व, निकाय और पुलिस के लिए तो हां, लेकिन बाकी के लिए क्या?

कई विभागों के कर्मचारी भी कर रहे फील्ड ड्यूटी, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा कोरोना योद्धा योजना का फायदा

इंदौर/भोपाल | DBStar

कोरोना से मौतों के मामले में आर्थिक सहायता को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने से प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। कोविड को अब तक प्राकृतिक आपदा नहीं माना है, इसलिए आम आदमी की मौत पर सरकारी इमदाद को लेकर आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं है। स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस और नगरीय निकायों के कर्मचारियों को तो फ्रंटलाइन वर्कर मान लिया गया है, अन्य विभागों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। भास्कर की पड़ताल बताती है कि आम आदमी की कोरोना से मौत होने पर भी उसके परिजन को अन्य योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता मिल सकती है।

और इधर... सरकारी विभाग के अलग-अलग प्रावधान

1. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि प्रदेश में कोविड-19 से पुलिसकर्मी की मौत होने पर उसके परिजन को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए और केंद्रीय कल्याण निधि से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मृतक के एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी।

2. कृषि मंत्री कमल पटेल ने घोषणा की है कि यदि किसी मंडी कर्मचारी की कोरोना से मौत होती है तो परिजन को 25 लाख की सहायता निधि दी जाएगी। यहां विरोधाभास यह है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में परिजन को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

3. ऊर्जा विभाग के ओएसडी एसके शर्मा ने 8 मई को जारी आदेश विभाग के साथ ही बिजली कंपनियों के स्थाई के साथ ही दैवेभो और आउट सोर्स कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का पात्र बना दिया गया है। इस आदेश को लेकर भी अधिकारी भ्रम में हैं।

4. शिक्षकों के बारे में शिक्षा विभाग से एक अलग आदेश निकलना बाकी है। प्रदेश में शिक्षा विभाग के कई कर्मचारियों की भी कोरोना से मौत हो चुकी है।

भास्कर EXPLAINER | जानिए... आम आदमी को कैसे मिल सकती है मदद

साक्षात्कार
बीएम शर्मा, रिटायर्ड आईएएस

राज्य सरकार ने किन्हें कोरोना योद्धा माना है, जिनकी मौत पर उनके परिजन को वह आर्थिक सहायता देती है?
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के बारे में जारी सर्कुलर में शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियां, निकाय आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी, अनुबंधित, दैवेभो, तदर्थ, आउटसोर्स कर्मियों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पात्र माना गया है।

यदि व्यापारी, मजदूर या निराश्रित की मौत कोविड से होती है तो परिजन को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई मजदूर कर्मकार कल्याण में पंजीकृत है या संबल कार्डधारी है तो उसे 2 से 4 लाख तक की मदद मिल सकती है। संबल कार्ड, राशन पात्रता पर्ची या कर्मकार पंजीयन नंबर धारक, मनरेगा मजदूर भी आर्थिक सहायता ले सकते हैं।

इसके लिए परिजन कहां संपर्क करें?
ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद व जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में आवेदन देना होगा।

यदि किसी के पास मजदूरी या संबल कार्ड नहीं है तो उसे मदद नहीं मिलेगी?
ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवेदन करना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को पहल करना चाहिए।

प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुलवाए गए थे। कहा गया था कि खाता खुलवाने वाले का बीमा भी होगा। क्या ऐसे खाताधारकों की कोविड से मौत होने पर परिजन को बीमा का लाभ मिलेगा?
ये खाते बैंकों में खोले गए थे। इसमें किसी भी सरकारी विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार को न बीमा राशि का पता है और न क्लेम को लेकर कोई क्लैरिटी है। बैंकों में भी ऐसे क्लेम का प्रावधान फिलहाल नहीं है। इस बारे में केंद्र ही बैंकों को निर्देश दे सकती है।

छात्रों ने जताई खुशी, अब सीबीएसई के विद्यार्थियों को इंतजार

माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12 वीं के विद्यार्थियों को थोड़ी राहत

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12 वीं के विद्यार्थियों को थोड़ी राहत मिली है कि परीक्षाएं अब स्थिति सामान्य होने पर होंगी। इससे विद्यार्थियों की परेशानी कुछ कम तो हुई है लेकिन अभी भी परीक्षा का टेंशन तो बना ही हुआ है। जहां एमपी बोर्ड से ये खबर आई है वहीं सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी अभी भी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थियों और स्कूल प्रशासन से हुई बातचीत पर यह तो पता चल गया है कि विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देना तो चाहते हैं पर अभी नहीं।

मॉडल स्कूल से डॉ गिरीश मैराल ने बताया कि कोरोना के इस संक्रमण काल में परीक्षा का आगे बढ़ा दिया जाना सही है। इससे सभी को राहत मिली है। लेकिन विद्यार्थियों के आगे की पढ़ाई पर जरूर कुछ असर पड़ सकता है। परीक्षाएं जब

भी होंगी सभी को सावधानी रख कर काम करना होगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो परीक्षा की तैयारी के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। साथ ही प्रशासन को भी चाहिए कि वो जुलाई तक परीक्षाएं करवा ही ले।

12वीं के विद्यार्थी अमन पटेल ने बताया कि उन्हें पता चला कि परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर होंगी। सच बताएं तो इस समय में परीक्षा होने पर टेंशन तो बहुत होता। इसलिए आगे बढ़ने पर खुशी है लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि परीक्षा होंगी कब। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके होने की भी अभी कोई तिथि घोषित नहीं कि गई है। सभी को स्थगित कर दिया गया है। इसलिए विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है।

एक अन्य विद्यार्थी उन्नति तिवारी ने बताया कि अभी कुछ भी पता नहीं है कि नीट कब होगी या जेईई कब होगी। कुल मिलाकर हम लोग इसी तनाव में रहेंगे की कभी भी परीक्षा हो सकती है। 12वीं की परीक्षा का होना बहुत जरूरी है। इससे आगे की पूरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा।

अनुग्रह राशि भुगतान में सहयोग नहीं कर रहे कलेक्टर

अन्य विभागों के पीड़ित भी हैं परेशान

भोपाल। कोरोना ड्यूटी करते दिवंगत हुए शिक्षक एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि पाना मुसीबत का कारण बन गया है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में जिलों के कलेक्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण इस प्रकार के हालात निर्मित हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से कोरोना योद्धाओं को मृत्यु उपरांत प्रदान की जाने वाली राशि का उनके परिजनों को शीघ्र भुगतान के लिए मांग की है।

शिक्षकों को राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा

प्रांताध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी कोविड के कार्य में लगाई गई है। उन सभी को मुख्यमंत्री ने कोरोना वारियर्स घोषित किया है। संघ इस के लिए उनका बहुत आभारी है। किंतु देखने में आया है कि कोरोना वारियर्स की मृत्यु उपरांत जो उन्हें 50 लाख की राशि मिलने की घोषणा की है। वो सभी कर्मचारियों को मिलने में विलंब हो रहा है। विशेषकर शिक्षकों को राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर के माध्यम से इसकी समीक्षा कराई जाए। कर्मचारी अधिकारी शिक्षक इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जान पर खेलकर कोविड कार्य में सेवा प्रदान कर रहे है। जिससे उनमें तथा उनके परिवार में बीमारी फेल रही है। इस के लिए प्रत्येक जिले में उनके बेहतर उपचार के लिए एक शेल बनाई जावे ताकि वो विना भय के इस कार्य को चिंता मुक्त होकर कर सके। उन्होंने कहा है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को बहुत जरूरत होने पर ही कोविड सेंटरों पर लगाया जाए जिससे बीमारी ज्यादा फैलने का खतरा कम हो सके।

पीड़ित परिजन अनुग्रह राशि पाने हो रहे परेशान

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में जिला संयोजक जितेंद्र चौहान का कहना है कि जो शिक्षक दिवंगत हुए हैं। उनके पीड़ित परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान कराने में कलेक्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं। भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर जैसे महानगरों के अलावा छोटे जिलों में भी इस प्रकार की परेशानी बनी हुई है। आए दिन दिवंगत शिक्षकों के पीड़ित परिजन अनुग्रह राशि पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय से लेकर ट्रेजरी तक के चक्कर काट रहे हैं लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार को इसके लिए तत्काल कलेक्टरो को पत्र जारी करना चाहिए।

कोरोनाकाल में शिक्षा व्यवस्था

12वीं परीक्षा पर केंद्र के साथ राज्य मिलकर करेंगे फैसला

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन और स्कूलों में कक्षाओं से जुड़ी रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई। 12वीं कक्षा की परीक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और राज्यों से सुझाव मांगे गए। इसके बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। सीबीएसई ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एक जून या इसके बाद समीक्षा की जाएगी और फिर लंबित बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फैसला किया जाएगा। कोरोना के चलते 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और मूल्यांकन की नीति की घोषणा कर दी गई है। अभिभावकों एवं छात्रों का एक वर्ग मांग कर रहा है 12 वीं की परीक्षा रद्द की जाए और मूल्यांकन की समान नीति लागू की जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि महामारी के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जैसी एजेंसियों ने शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन जारी रखा और जेईई और नीट (स्नातक) जैसी परीक्षाएं भी कराईं। हमारी प्रतिबद्धता यह है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 24 करोड़ छात्र-छात्राओं की शिक्षा जारी रहे।

15 दिन पहले मिलेगी सूचना

लाखों छात्रों परीक्षा के होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में सरकार ने छात्र के लिए आदेश जारी किया है कि छात्रों को परीक्षा होने से 15 दिन पहले सीबीएसई द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

विद्युत नियामक आयोग का ऐतिहासिक फैसला

पेंशन ट्रस्ट में ₹750 करोड़ जमा न करने पर बिजली कंपनियों के एमडी पर जुर्माना

भास्कर न्यूज . भोपाल| विद्युत नियामक आयोग सामान्य तौर पर आम जनता की बिजली के टैरिफ बढ़ाए जाने की शिकायतों पर दरें निर्धारण करता है, लेकिन पहली बार आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला मध्य, पूर्व, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी द्वारा पेंशन ट्रस्ट में 750 करोड़ रुपए जमा न कराए जाने को लेकर है। आयोग के अध्यक्ष एसपीएस परिहार ने अपने फैसले में चारों कंपनियों के एमडी से 11 जून तक 1-1 लाख रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। यानी चारों कंपनियों के एमडी को तय तारीख में 4 लाख रु आयोग में जमा करने होंगे। शेष|पेज 11 पर

बकाया जो पेंशन ट्रस्ट में नहीं हुआ जमा

वर्ष	बकाया राशि (करोड़ में)
2017-18	120
2018-19	210
2019-20	210
2020-21	210

यह है मामला • बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से जो बिजली बिल की वसूली करती हैं, उसमें एक हिस्सा बिजली प्रदाय करने में अहम भूमिका निभाने वाले बिजली कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन का रहता है। उपभोक्ताओं से ली गई इस राशि को नियम के हिसाब से बिजली कंपनियों को पेंशन ट्रस्ट में जमा कराना होता है। लेकिन चारों कंपनियों ने 2017 के बाद पेंशन ट्रस्ट में राशि जमा नहीं कराई, जिससे मौजूदा कार्यरत कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने पर उनकी पेंशन का खतरा मंडरा गया। बिजली कंपनियों में काम कर रहे 20 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का रिटायरमेंट 2025-26 तक होना है। इस मामले को लेकर चारों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ झंडा बुलंद करते हुए आयोग में शिकायत की थी। स्थिति यह है कि पेंशन ट्रस्ट में 17 मई को महज 30 करोड़ रुपए ही जमा थे, जबकि 750 करोड़ रुपए जमा होना था।

1 जून को सीबीएसई बोर्ड करेगा फैसला

12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द
पीएम को पेरेंट्स ने पत्र लिखा

नई दिल्ली। लाखों छात्र सीबीएसई, सीआईएससीई बोर्ड की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 आयोजित होने पर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने की संभावना अधिक है क्योंकि परीक्षा रद्द करने के लिए जोर जोर से बढ़ता जा रहा है। इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी से 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए सुझाव दिया कि छात्रों का मूल्यांकन उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो कॉलेजों में एक योग्यता परीक्षा हो सकती है।

- मांग-छात्रों का मूल्यांकन उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर हो

कोविड से बेसहारा बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया तय

नई दिल्ली| सरकार ने कोरोना के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नोटिस में कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चों को गोद लेने की पेशकश के मैसेज से बचना चाहिए। जिन बच्चों ने मां-पिता को खो दिया है। उन्हें जिला बाल कल्याण समिति के सामने 24 घंटे में पेश किया जाएगा।

सहायक शिक्षिका के निधन पर शोक

सतना| सोहावल निवासी अधिवक्ता शाहिद खान की पत्नी सहायक शिक्षिका नूरजहां खान के आकस्मिक निधन पर अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। श्रीमती खान का निधन 15 मई को हो गया था। शोक व्यक्त करने वालों में शिक्षक दिनेश मिश्रा, राजेन्द्र मिश्रा, अरूण मिश्रा, भूपेन्द्र बागरी, कमलाकांत विश्वकर्मा, मनमोहन मिश्रा, कुसुम यादव, कृष्णा मिश्रा, गीता सिंह, मनीष सोनी, आरती तिवारी, सरोजनी तिवारी, मयूरिका श्रीवास्तव, आशा सिंह, जीपी रमेश मिश्रा, एजीपी हनुमान शुक्ला, अधिवक्ता राजेश पांडेय, यशवंत मिश्रा, पीसी निगम, वीरेन्द्र सिंह, सुरेश तिवारी, मानसमणि, दीपक राय, असलम खान, आरयू सिद्दीकी, फिरोज खान, प्रहलाद सिंह, राजीव शुक्ला, हंसराज सिंह, सुधीर निगम, मनोज पांडेय, राकेश शुक्ला, सोहावल निवासी बृजेश सिंह, बिज्जू सिंह, काशी पटनहा, शिवकुमार, दिनेश पांडेय, राजा चतुर्वेदी, विश्वनाथ, भगवानदास, नसीम, रमाकांत दुबे, अनिल दुबे, मुक्ति तिवारी, धीरेद्र गौतम, पुरूषोत्तम पाठक, अरविंद पटनहा, जाकिर हुसैन, शौकत हुसैन, मो. इस्माइल, शहजाद, इब्राहिम, रकीफ, मो. इबरार, अख्तर हुसैन, राजू, मुमताज बाबू, मो. कादिर, उमेश, संजय और अरशद शामिल रहे।

यूजी-पीजी की परीक्षाएं जून-जुलाई में

भास्कर न्यूज,| भोपाल

कोरोना की वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाओं पर भी सीधा असर पड़ा है। अब स्नातक स्तर की परीक्षा जून और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। परीक्षाएं देर से होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अब तक प्रवेश प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू नहीं हुई है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की दलील है कि 12वीं के परीक्षा परिणाम के बाद ही स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित होने के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू होंगे।

ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र राज्यों को देगा फंड

ब्यूरो/भास्कर न्यूज/ नई दिल्ली | कोरोना के दौर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को फंड मुहैया कराएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में पोखरियाल ने बताया कि समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को 5,228 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जबकि 2,500 करोड़ रुपए जल्द और जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने पांच मई को कंप्रिहेंसिव कोविड रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट जारी किया था।

परीक्षा फार्म भरने को लेकर असमंजस में परीक्षार्थी

कार्यालय प्रतिनिधि, रीवा| अवधेश प्रताप इक्षसह विश्वविद्यालय द्वारा गत दिवस परीक्षार्थियों के लिए १५ से ३० मई तक परीक्षा फार्म भरने की तिथि तय की गई है। लेकिन लॉकडाउन अवधि बढऩे के कारण परीक्षार्थी परीक्षा फार्म नहीं भर पा रहे हैं। हालात यह है कि छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि वह विवि द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर परीक्षा फार्म भर भी पाएंगे या नहीं। गौरतलब है कि विवि द्वारा गत दिवस परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि तय की थी। लेकिन विवि द्वारा जो तिथि तय की गई उसमें परीक्षार्थी परीक्षा फार्म नहीं भर पा रहे हैं। विवि द्वारा जो तिथि तय की गई है उसके अनुसार परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के आगामी ३० मई तक परीक्षा फार्म भर सकेंगे। जिले में कोरोना इफेक्ट को देखते हुए प्रशासन द्वारा भी आगामी ३० मई तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब जिले में लॉकडाउन लगा होने के कारण परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा फार्म भरने में समस्या आ रही है। विवि सूत्रों की माने तो जिले में लॉकडाउन लगा होने की समस्या को देखते हुए विवि प्रशासन द्वारा परीक्षा फार्म भरने की तिथि में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति की उठी मांग

जवा| आजाद अध्यापक संघ जवा के अध्यक्ष प्रमोद चतुर्वेदी ने अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा मे नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा नियम 2018 के तहत नियुक्ति की कार्यवाही से जवा सहित रीवा जिले के पांच सैकड़ा अध्यापकों को अभी तक लोकायुक्त प्रकरण के नाम पर लंबित रखा गया है। जिसकी प्रकिया पूरे प्रदेश में प्रचलन में है। इस समय जहां एक ओर वैश्विक महामारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वहीं स्कूलों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग भी इससे अछूता नही है और आये दिन शिक्षक भी कोविड 19 संक्रमित होकर मौत के शिकार हो रहे है। जो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। रीवा जिले के ऐसे लगभग पांच सैकड़ा शिक्षक हैं, जिसकी नवीन सम्वर्ग में नियुक्ति नहीं होने से उनको शासन के गाइड लाइन अनुसार जीआईएस बीमा आदि की राशि कटौती नही हो पा रही है तथा उनको सातवें वेतनमान व राज्य शासन के कर्मचारी होने से वंचित रखा गया है। मांग करने वालों में प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह, प्रान्तीय प्रवक्ता बालेंदु शेखर द्विवेदी, पुष्पेंद्र द्विवेदी, दया शंकर मिश्रा, संजय सिंह, इंद्रलाल वर्मा, अगमलाल सिंह, तरुण पांडेय, अशोक कुमार पांडेय, चंद्रमा सिंह, रावेंद्र सिंह, अनिल मिश्रा, शिवमोहन उपाध्याय, सत्येंद्र त्रिपाठी, राजेन्द्र सिंह चौहान, धर्मराज वर्मा, दयानंद द्विवेदी, रमेश तिवारी, सुमित्रा देवी, धीरेश द्विवेदी, विक्रमादित्य कोरी सिंह आदि शामिल हैं।

विद्यालयों को 30 तक देनी होगी ओएमआर शीट्स

10वीं की प्रायोगिक परीक्षा के माशिमं ने मांगे अंक, समन्वयक संस्था को करनी होगी कार्यवाही

जागरण, रीवा। जिले के विद्यालय कक्षा 10वीं की आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षाओं की ओएमआर शीट्स 30 मई के पहले अनिवार्यतः तैयार करना होगा। उक्त दिनांक तक सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय शासकीय विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक 1 समन्वयक संस्था में शीट्स बंद लिफाफे में जमा करेंगे। फिर समन्वयक संस्था को 3 जून तक अनिवार्य रूप से माशिमं मुख्यालय उक्त लिफाफे प्रेषित करने होंगे। इस बाबत माशिमं ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर शीट्स भेजने का उक्त कार्यक्रम माशिमं ने रीवा व शहडोल सम्भाग के सभी विद्यालयों हेतु निर्धारित किया है। इस प्रायोगिक परीक्षा कार्य हेतु किसी भी विद्यालय को राशि भुगतान करने पर भी माशिमं ने फिलहाल रोक लगा दी है। कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा कराने माशिमं द्वारा पृथक से सूचना जारी की जायेगी।

गौरतलब है कि जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत् 10वीं, 12वीं के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बाबत माशिमं ने गत 7 मई को आदेश प्रसारित कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब 12वीं की स्थगित परीक्षा कराने हेतु आगामी तिथि माशिमं द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। जबकि कक्षा 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंक के आधार पर उत्तीर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के चलते माशिमं ने यह प्रक्रिया अपनाई है।

जिले के 539 विद्यालयों के छात्र शामिल : बता दें कि सत्र 2020-21 की कक्षा 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी माशिमं कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। जबकि 10वीं, 12वीं की मुख्य प्रायोगिक परीक्षा गत 17 अप्रैल से माशिमं के निर्देश पर अब तक चलती रहीं। हालांकि उक्त परीक्षा के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए थे और 20 मई तक छात्रों को विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी थी। वहीं, स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ ही केंद्र में होनी थी। बहरहाल, अब माशिमं ने उक्त गतिविधि पर विराम लगा दिया है। बता दें कि इस प्रक्रिया में जिले के 539 सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र शामिल हो रहे हैं। 10वीं, 12वीं के इन छात्रों की परीक्षा पूर्व के तय कार्यक्रम अनुसार मार्च महीने में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए माशिमं निरंतर परीक्षा कार्यक्रम टालता जा रहा है। अब जून महीने में भी कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा का होना मुश्किल लग रहा है।

स्कूलों की तरह कालेज के छात्रों भी दिया जाए जनरल प्रमोशन

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

नगर प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डा. विक्रांत भूरिया ने स्कूलों की तरह कालेजों के छात्रों को भी जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की है। उन्होंने यह मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। भूरिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। भूरिया ने लिखा, स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत किए जाने का फैसला शासन द्वारा किया गया है। इसी तरह का निर्णय स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए भी लिया जाए। उन्होंने इस संबंध में जल्दी आदेश जारी किए जाने की मांग की है। भूरिया ने इसके लिए डेढ़ साल से फैली कोरोना आपदा का हवाला दिया है। भूरिया ने कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं और परीक्षा कराने के नाम पर उनकी जान को खतरे में डालना उचित नहीं है।

कोविड-19 में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की देखभाल करेगी सरकार

सतना, (नव स्वदेश)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के संकट काल में हमारे कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब हम लोगों से घरों में बने रहने की अपील कर रहे हैं, तब ये कर्मचारी भाई-बहन दिन-रात मैदान में अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे में कई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। काम करते हुए हमारे कई कर्मचारी भाई-बहन कोविड-19 के दौरान हमसे बिछड़ गए, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनके परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए दो योजनाएँ बनाई जाएंगी। यह हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना तथा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना।

कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक एवं सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संकट की स्थिति में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का संबल बनेगी।

इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार इत्यादि कर्मी भी सम्मिलित होंगे। अनुकम्पा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है ताकि इन परिवारों के जो आश्रित भाई-बहन हैं, उन्हें राहत मिल सके और उनकी आजीविका चलती रहे।

शिक्षक ने बरती लापरवाही खुली जेल से भागे लोग

लापरवाह शिक्षक को एडीएम ने थमाया नोटिस

श्योपुर, ब्यूरो।

कोविड संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को घरों में रहने की नसीहत देने के साथ पुलिस द्वारा अकारण घूमने वाले लोगों को खुली जेल में बंद कर लॉकडाउन का पालन कराने के प्रयास किये जा रहे है, लेकिन कुछ लापरवाह लोगों की मनमानी के चलते यह प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही लापरवाही का मामला उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ एक शिक्षक का सामने आया है, जिसकी लापरवाही से खुली जेल में बंद 20 लोग भाग गए।

मालूम हो कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक शैलेन्द्र सिंह तोमर की 15 मई को बाईपास रोड स्थित बालिका छात्रावास में बनाई गई खुली जेल में ड्यूटी लगाई गई थी। नियमानुसार शिक्षक को प्रतिदिन खुली जेल में बंद होने वाले लोगों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देनी थी। शिक्षक की लापरवाही के कारण उक्त जेल से सोमवार को 20 लोग भाग निकले। इसी लापरवाही पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक शैलेंद्र सिंह तोमर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा में उचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है

शिक्षक की लापरवाही की वजह से खुली जेल में बंद लोग भाग गए हैं। शिक्षक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

रुपेश उपाध्याय
अपर कलेक्टर, श्योपुर

प्रतिबंध के बाद भी कुछ स्थानों में चल रही कोचिंग

बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे कोचिंग संचालक

जागरण, रीवा। जिले में कोविड-19 से बचाव के उपायों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बात और गम्भीर हो जाती है, जब नियमों को तोड़ने में निजी कोचिंग संचालक आगे चल रहे हों। खबर है कि शहर के ढेकहा, पड़रा, द्वारिका नगर जैसे कुछ इलाकों को बच्चों की कोचिंग लगाई जा रही है। प्रत्येक कोचिंग में 15-20 बच्चों की उपस्थिति रहती है। प्रशासन की आंखों से बचकर कोचिंग संचालक अपना धंधा चला रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कोचिंग में कई सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के बच्चे भी पहुंच रहे हैं। यानि प्रशासन के नुमाइंदों को मामले की खबर है। फिर भी मामले को अब तक गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु

जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान गत 14 अप्रैल से बंद हैं। पूर्णतः लॉकडाउन होने के बाद भी निजी कोचिंग संचालक निर्देशों को नहीं मान रहे। बता दें कि गत वर्ष भी प्रशासन ने कोरोना के चलते ही लॉकडाउन किया था। तब भी कुछ कोचिंग संचालन नियम तोड़ने पर आमदा थे। अब इस बार फिर कोचिंग संचालक नियमों को मानने तैयार नहीं हैं। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। चूंकि इन जगहों बच्चे समूह के रूप में एकत्रित होते हैं और बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होता है। लिहाजा बच्चों-बूढ़ों को वायरस से बचाने की कवायद जारी है, जिस पर कोचिंग संचालक पलीता लगाने लगे हैं।

कुछ जिम और डांस क्लास भी चला रहे

जानकारी के मुताबिक शहर में कुछ जिम संचालकों ने भी बैकडोर खोल दिया है। कोचिंग संचालकों की तरह मोटी फीस लेकर जिम संचालक लोगों को बुला रहे हैं। इस कारण कोरोना महामारी के फैलने का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। द्वारिका नगर, सिरमौर चौक के पास व अन्य कुछ स्थानों में जिम का संचालन भी होने लगा है। ऐसे ही नेहरू नगर, रसिया मोहल्ला जैसे कुछ क्षेत्रों में सुबह, दोपहर डांस क्लास भी शटर बंद करके चल रही है।

कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग

भोपाल। स्कूल शिक्षा-जनजातीय कार्य विभाग गणना करने में लगे हैं। वहीं, कोरोना महामारी में

मांग

ड्यूटी के दौरान दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुग्रह राशि तक नसीब नहीं हो रही है। समग्र शिक्षक संघ ने यह आरोप लगाते हुए अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि प्रदेश भर में ड्यूटी के दौरान शिक्षक संक्रमित होकर मृत हो चुके हैं, ऐसे शिक्षकों को विभाग द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।भोपाल।राजधान

ढाई लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट और एग्जाम पर संकट

परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

भास्कर ब्यूरो| भोपाल

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रथम से 8 वे सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में पूरी करा ली गई, जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सके हैं। चुनिंदा विद्यार्थियों के आठवें सेमेस्टर के रिजल्ट जारी किए गए हैं। जबकि ढाई लाख विद्यार्थी रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आगामी सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर आरजीपीवी में कोई तैयारी नहीं है। आरजीवीपी के प्रभारी परीक्षा नियंत्रक प्रभात पटेल और रजिस्टर आर एस राजपूत ढाई लाख विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आरजीवीपी ने बीई, बीटेक, एम सी ए ,एमई ,एमटेक, आर्किटेक्चर सहित अन्य विषयों की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में पूरी करा ली थी। परीक्षा हुए 2 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन रिजल्ट तैयार करने के लिए दोनों अफसर प्रोफेसरो से सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन तक नहीं करा सके हैं। जबकि आरजीपीपी को ऑनलाइन वैल्यूएशन कराना है।हालांकि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आठवें सेमेस्टर के पूर्व विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं। क्योंकि उक्त रिजल्ट 2 माह पूर्व तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अनिल कुमार सिंह द्वारा तैयार कराए गए थे। इसके बाद से रिजल्ट को लेकर अधिकारियों में कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं।

उत्तर पुस्तिकाएं तक नहीं खोज पाए

फरवरी-मार्च में विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक से कराई गई थी जिसमें विद्यार्थियों की कॉपियां कॉलेजों में जमा कराई गई थी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन कराने के लिए नियंत्रक प्रभात पटेल विद्यार्थियों की कॉपियां तक नहीं तलाश पाए हैं। कॉपियों के अभाव में उनका मूल्यांकन होना मुश्किल है।

जून-जुलाई में करानी हैं परीक्षाएं

शासन के आदेश के मुताबिक सभी विश्वविद्यालय को जून और जुलाई में अपनी परीक्षाएं पूरी कराना है। शासन ने ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं कराने के आदेश जारी कर रखे हैं। आरजीवीपी अपने विद्यार्थियों की ऑनलाइन एग्जाम लेगा। ऑनलाइन परीक्षा कराने को लेकर परीक्षा नियंत्रक प्रभात पटेल और रजिस्टर आर एस राजपूत ने कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि रिजल्ट के अभाव में विद्यार्थी आगामी सेमेस्टर की परीक्षाओं में कैसे शामिल हो सकता है।

ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने फिर शुरू हुई कवायद

उच्च शिक्षा विभाग ने निःशुल्क वीडियो व्याख्यान बनाने शिक्षकों को किया आमंत्रित

जागरण, रीवा। महाविद्यालयों के छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने अब फिर से कसरत शुरू हुई है। जिले के सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग ने आमंत्रित किया है। इन शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने वीडियो व्याख्यान बनाने विभाग ने कहा है। इसके बदले किसी भी शिक्षक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यह भी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। हाँ, वीडियो व्याख्यान बनाने हेतु विभाग संबंधित शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दे सकता है। इस बाबत विभाग ने गूगल लिंक जारी की है, जिसमें इच्छुक शिक्षकों से 5 जून तक आवेदन मांगे गए हैं।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी को रोकने प्रदेश में लॉकडाउन है। जिले में विगत 14 अप्रैल

से सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद हैं। यानि महीने भर से छात्रों ने कक्षाओं की शक्ल नहीं देखी। हालाकि विभाग व महाविद्यालयों ने सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के जरिये अध्ययन करने की बात कही है परंतु सिलेबस के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन सम्पूर्ण ब्यौरा नहीं मिल पा रहा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ही अब विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही की जा रही है। ताकि नियत समय पर परीक्षा कराने से पहले छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो सके। बता दें कि गत वर्ष भी लॉकडाउन रहा। लिहाजा विभाग ने वीडियो व्याख्यानाओं की कैटेलॉगिंग करवाई, जो असफल रही। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने हेतु अन्य कई प्रयोग विभाग ने किए, जो लगभग असफल रहे। अब एक बार फिर नये सिरे से विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है।

वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम का ही बनाये कंटेट

पत्र में विभाग ने कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के 18 विषय दिए हैं, जिनके वीडियो व्याख्यान बनाये जाने हैं। विभाग ने यह विशेष रूप से कहा है कि विषयों के वीडियो व्याख्यान वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार ही दिए जाये। प्रत्येक प्रश्न पत्र की प्रत्येक इकाई को 6 मुख्य भागों में विभाजित करना होगा और प्रत्येक भाग का 30 से 40 मिनट का व्याख्यान शिक्षकों को बनाना होगा।

विभागीय पोर्टल पर अपलोड होंगे वीडियो : विभाग ने जारी पत्र में उल्लेखित किया है कि इन वीडियो व्याख्यानों पर शिक्षकों का स्वामित्व नहीं होगा। विभाग इसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर देगा, जिसे विषयवार छात्र कहीं से भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो व्याख्यानों में आवश्यकतानुसार पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन, एनीमेशन आदि का प्रयोग करने की सलाह भी विभाग ने दी है। वीडियो व्याख्यान बनाने सारी तकनीकी सामग्री का उपयोग शिक्षकों को स्वयं करना होगा। जरूरत पड़ने पर रिकार्डिंग रूम या अन्य तकनीकी सहायता विभाग मुहैया करा सकता है।

अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं छात्र

विभाग की उक्त कार्यवाही से छात्रों को कितना फायदा होगा, यह तो वक्त ही बतायेगा। फिलहाल सभी छात्र पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा विभाग के निर्देश पर परीक्षा तैयारी शुरू कर दी गई है। सत्र 2020-21 की परीक्षा अगले माह तक प्रारम्भ हो सकती है। हालांकि परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के तहत ही होनी है। फिर भी कुछ होनहार छात्र पाठ्यक्रम पूरा न होने व ठीक से पढ़ाई न हो पाने को लेकर चिंतित हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने लिए कर्मचारी हितैषी निर्णय-कमर्चारी संगठनों ने माना आभार

विशेष संवाददाता ■ भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी नियमित, स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर और आउट सोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति और अनुग्रह राशि देने लागू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिये प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनका यह सराहनीय और कर्मचारी हितैषी निर्णय है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ कर्मचारियों के हित में यह योजनाएँ लागू की गई हैं। कोरोना महामारी के भीषण दौर में भी कर्मचारी परिवारों की फिक्र करके मुख्यमंत्री श्री चौहान की कर्मचारी हितैषी छवि पुन- प्रकट हुई है। यह योजनाएँ कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के लिये वरदान साबित होंगी और उन्हें सुदृढ़ आर्थिक संबल प्रदान करेंगी।

कर्मचारी संगठनों ने कहा कि इन योजनाओं में खास बात यह है कि योजना में नियमित, दैनिक वेतनभोगियों, स्थाई कर्मियों, संविदा कर्मी और कलेक्टर दर इत्यादि सभी प्रकार के कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति और अनुग्रह राशि मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक बता रहे हैं जनता को रोग मुक्त रहने के गुर

खुश कैसे रहा जाए शिक्षा विभाग से योग प्रशिक्षण प्राप्त टीचरों ने बताए तरीके

भोपाल(आरएनएन)। मध्यप्रदेश में नासूर बन रही कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों ने जागरूकता लाने की अनोखी पहल की है। शिक्षा विभाग से योग प्रशिक्षण प्राप्त टीचर ग्रामों में जनता को रोग मुक्त और खुश रहने के अनेक तरीके बता रहे हैं।

इस अभियान में ज्यादातर वही शिक्षक शामिल हैं।जिन्होंने शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय योग केंद्र से प्रशिक्षण लिया है। इन प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अपने-अपने जिलों में स्कूल बार शिक्षकों को योग की ट्रेनिंग दी गई है। यही शिक्षक ग्रामों में जनता को कोरोना से लड़ने की ताकत बता रहे हैं। ग्रामों में शिक्षक जनता को व्हाट्सएप पर वीडियो डालकर बता रहे हैं कि वह प्रमुख योगिक क्रियाओं को करके बीमारी से पूरी तरह बच सकते हैं। इस समय ग्रामों में जनता को अनुलोम विलोम भ्रमरी प्राणायाम सूर्य नमस्कार भुजंगासन कैची आसन जैसी आसान योगिक विधियां बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इन छोटी-छोटी क्रियाओं को करने से मन जहां तनाव से मुक्त रहेगा वही लोगों के बीच बैठे बीमारी की चिंता भी दूर होगी। शिक्षकों ने कोरोना ड्यूटी करने के साथ-साथ ज्यादातर ग्रामों में अपने स्वविवेक से यह काम प्रारंभ किया है। योग विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि ऐसे समय में योग की क्रियाएं की जाए तो फिर कोरोना जैसी महामारी से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की आंतरिक शक्ति इससे मजबूत रहेगी और वह बीमारी से डटकर मुकाबला करने में सक्षम होगा।

ऐसे समय में योग्य देगा मानव शरीर को बड़ी ताकत

शासकीय केंद्र में प्रभारी देवीदयाल भारती का कहना है कि ऐसे समय में योगिक क्रियाएं मनुष्य को बड़ी ताकत प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया है कि शिक्षकों को राज्य स्तर से लगातार योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना का संकट है इस कारण ऑनलाइन तरीके से जिला बार शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हीं शिक्षकों द्वारा गांव गांव खेल रही कोरोना महामारी को भगाने के लिए लोगों में योगिक क्रियाएं ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की जा रही है। उनका कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब योग के सकारात्मक परिणाम इस भीषण संकट में सामने आएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार भी योग से निरोग रहने का कार्यक्रम अनवरत रूप से चला रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम से भी कोरोना को खत्म करने में बड़ी मदद मिल रही है।

ज्यादातर राज्यों ने बोर्ड परीक्षा को बताया अहम, कराने पर जोर

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को रद करने की उठ रही मांगों के बीच ज्यादातर राज्यों ने इन परीक्षाओं को अहम बताया है और इन्हें कराने का सुझाव दिया है। हालांकि इसके लिए किसी भी उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया है। इस बीच, राज्यों ने छात्रों की आनलाइन पढ़ाई की राह में आड़े आ रहे मोबाइल फोन, टैबलेट आदि का मुद्दा भी उठाया। साथ ही केंद्र से छात्रों को इसे मुहैया कराने के लिए मदद की भी मांग की। इस दौरान कुछ राज्यों ने इनोवेशन फंड से मदद का सुझाव दिया।

कोरोना संकट काल में राज्यों ने यह सुझाव शिक्षा से जुड़े विषयों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ चर्चा में दिया। इस बीच, परीक्षा के समर्थन में ओडिशा सबसे पहले आगे आया। बाद में दूसरे राज्यों ने भी उसका समर्थन किया। फिलहाल निशंक ने साफ किया कि जो भी फैसला लिया जाएगा, वह छात्रों के व्यापक हितों को देखते हुए ही लिया जाएगा।

राज्यों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को फिलहाल 5228 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। जो आनलाइन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। इस बीच केंद्र ने जल्द ही राज्यों के साथ ही समग्र शिक्षा की योजना को अंतिम रूप के लिए चर्चा की जानकारी भी दी। मंत्रालय ने इसके साथ ही राज्यों को अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी 25 सौ करोड़ की राशि जारी करने का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि इस पैसे से राज्य आनलाइन पढ़ाई से वंचित छात्रों को मोबाइल फोन या टैबलेट जैसी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। स्कूली शिक्षा से जुड़ी संस्था असर की ओर से पिछले साल अक्टूबर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी करीब 40 फीसद छात्रों के पास मोबाइल या आनलाइन पढ़ाई के लिए कोई दूसरा संसाधन नहीं है।

शिक्षा पर व्यापक सोच

- **केंद्र का मदद का भरोसा, समग्र शिक्षा के लिए 5228 करोड़ रुपये किए जारी**
- **अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी 25 सौ करोड़ जारी करने का भरोसा**

मेडिकल एंट्रेंस: एक अगस्त को प्रस्तावित है नीट, 15% एआईक्यू के लिए मुश्किल कॉम्पिटिशन

नीट: सामान्य वर्ग में 5 हजार रैंक तक मिलता है टॉप कॉलेज

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक के बाद एक सभी परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) यूजी 1 अगस्त 2021 को होना फिलहाल तय माना जा रहा है। मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट देश में सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नीट आयोजित करता है। एनटीए की ओर से अभी तक इस टेस्ट के स्थगित होने की सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल इस परीक्षा में ढाई महीने का वक्त बाकी है। अगर देश में कोरोना की स्थितियों पर नियंत्रण कर लिया गया तो संभवतः यह परीक्षा अपने तय समय पर ही आयोजित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नीट-यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। इस बीच देश के प्रमुख कॉलेजों की 2020 की कट ऑफ रैंक भी उन्हें जाननी चाहिए। ताकि वे उसी अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के अंकों के आधार पर खुद का आंकलन करना चाहिए। सभी सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 15 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू)) के लिए आरक्षित हैं और शेष 85 फीसदी सीटें राज्य कोटा के तहत आरक्षित हैं। 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के लिए आरक्षित सीटों का कट ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जारी करती है। स्टेट के लिए आरक्षित सीटों का कट-ऑफ राज्यों की संबंधित संस्थाएं जारी करती हैं। अब एम्स व जिपमेर जैसे संस्थानों में भी नीट की कट ऑफ के आधार

पर दाखिला मिलता है। पहले एम्स व जिपमेर अपना एंट्रेंस अलग करवाते थे। हालांकि हरेक कॉलेज की एडमिशन की पात्रता अलग अलग होती है। नीट की रैंक के साथ पात्रता पूरी करने पर ही दाखिला मिलता है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के लिए पात्रता अलग-अलग होती है।

आसान भाषा में समझिए कट-ऑफ रैंक के गणित को

अच्छा कॉलेज पाने के लिए स्टूडेंट्स को पांच हजार रैंक में आना जरूरी होता है। पिछले साल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक 90 रही थी। यानि इस कैटेगिरी में 91 व इससे अधिक रैंक पाने वाले छात्रों को यह कॉलेज नहीं मिल पाया था। वहीं अनुसूचित वर्ग में 1475 रैंक ही एडमिशन बंद हो गए। क्लोजिंग रैंक वह होती है, जिस पर एडमिशन बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की जनरल कैटेगिरी में पिछले साल क्लोजिंग रैंक 324 रही थी।

यूपीएससी प्रीलिम्स

टलने से नहीं आएगा अगले साल की परीक्षा पर असर

कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए यूपीएससी ने साल 2021 के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को स्थगित कर दिया है। पहले यह परीक्षा 27 जून को आयोजित होने वाली थी, जो अब 10 अक्टूबर को होगी। अगर कोरोना की स्थिति पर समय रहते काबू पा लिया गया तो एग्जाम अपनी नई तारीख पर ही होंगे। कुल 822 पदों के लिए इस बार आवेदन मांगे गए थे। हालांकि पिछले साल के इंटरव्यू भी अभी नहीं हुए हैं। स्थिति 2020 जैसी ही है।

सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक्सपर्ट सत्री कुमार का कहना है कि इतने लंबे समय के लिए प्रीलिम्स को इसलिए स्थगित किया गया है क्योंकि पिछले साल का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। यूपीएससी की प्रक्रिया पर अगर गौर करें तो आयोग प्री की परीक्षा से महीने भर पहले किसी भी हाल में पिछले साल का फाइनल रिजल्ट जारी कर देता है ताकि परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के सामने स्पष्टता रहे कि उन्हें इस बार भी परीक्षा में बैठना है या नहीं। इस परीक्षा के स्थगित होने से अगले साल के एग्जाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल प्रीलिम्स जून में होना था लेकिन कोरोना के कारण उसे अक्टूबर में आयोजित किया गया था। हालांकि उसके स्थगित होने से इस साल के प्री पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती तो इस वर्ष का प्री भी जून में ही होता। परीक्षा स्थगित होने से बस महीने भर का फर्क आएगा। उधर, पिछले साल से ही यूपीएससी का परीक्षा चक्र गड़बड़ा गया है। साल 2020 की सीएसई परीक्षा से मिलने वाले प्रशासनिक अधिकारी मई 2021 तक नहीं मिले हैं। इंटरव्यू स्थगित होने के कारण यह प्रक्रिया लंबित ही चल रही है। अब 2021 की परीक्षा से मिलने वाले अधिकारी 2022 में ही मिल पाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम को समय पर करवाने के लिए जाना जाता है। लेकिन कोविड के चलते पूरी प्रक्रिया में रुकावट आई है।

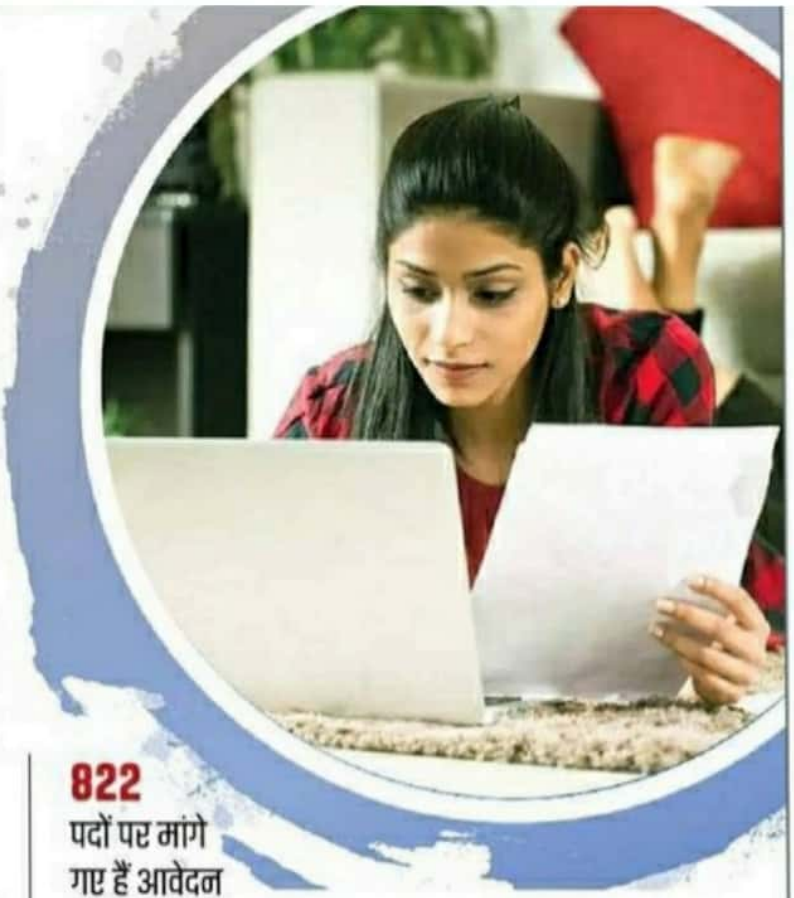

822
पदों पर मांगे गए हैं आवेदन

2020 की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है पूरी

2021 की प्रोसेस भी साल 2022 में होगी पूरी

साल 2020 के इंटरव्यू पहले ही हो चुके हैं स्थगित

कोरोना ने यूपीएससी के कई एग्जाम्स पर असर डाला है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज व यूपीएससी-2020 के इंटरव्यू पहले ही स्थगित कर दिए गए हैं। इंटरव्यू का तो लगभग पूरा शेड्यूल तय हो गया था। वहीं सीएमसी परीक्षा भी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही स्थगित कर दी गई थी।

अब तक नहीं मिल पाए सीएसई 2020 के अफसर

साल 2020 में शुरू हुई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी तक देश को नए प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं मिल पाए हैं। कोविड के चलते 2021 की प्रक्रिया भी 2022 में पूरी होती नजर आ रही है। 2021 में भी प्रीलिम्स के बाद मेंस फिर इंटरव्यू होगा जिसमें समय लगेगा। इसके बाद जॉइनिंग मिलेगी।

दिसंबर अंत तक हो सकता है यूपीएससी मेंस एग्जाम

छात्रों को पिछले साल की तरह ही इस साल भी प्री व मेंस परीक्षा के बीच तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। करीब दो से ढाई माह का समय इन एग्जाम्स के बीच दिया जाता है। अक्टूबर में प्रीलिम्स होने पर लगभग दिसंबर अंत तक मेंस एग्जाम का आयोजन करवा लिया जाएगा। उम्मीदवार यह तनाव न रखें कि उन्हें मेंस की तैयारियों के लिए कम समय मिलेगा।

JOBS

नेशनल एरोस्पेस लैबोरेट्रीज
पदः टेक्निकल असिस्टेंट व अन्य
पद संख्याः 26
आवेदनः ऑनलाइन
अंतिम तिथिः 21 मई, 2021
https://www.nal.res.in/

नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
पदः प्रोजेक्ट असिस्टेंट व अन्य
पद संख्याः 54
आवेदनः ऑनलाइन
अंतिम तिथिः 24 मई, 2021
https://www.ngri.org.in/

ऑयल इंडिया लिमिटेड
पदः कॉन्ट्रैक्चुअल ड्रिलिंग हैडमैन व अन्य
पद संख्याः 119
आवेदनः वॉक-इन प्रैक्टिकल
अंतिम तिथिः 24 मई से 22 जून
www.oil-india.com

नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया
पदः डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल)
पद संख्याः 41
आवेदनः ऑनलाइन
अंतिम तिथिः 28 मई, 2021
https://nhai.gov.in/

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट
पदः डायरेक्टर व अन्य
पद संख्याः 17
आवेदनः ऑफलाइन
अंतिम तिथिः 31 मई, 2021
http://iamrindia.gov.in/

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर
पदः टेक्नीशियन व अन्य
पद संख्याः 7
आवेदनः ऑनलाइन
अंतिम तिथिः 31 मई, 2021
https://serc.res.in/

कोरोना इफेक्ट - पांच हजार स्कूल वैन चालकों पर रोजी-रोटी का संकट, क्योंकि...

421 दिन से थमे हैं कमाई के पहिए

भोपाल | DBStar

संकट... बच्चों की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं, घर चलाने बीवी के गहने तक गिरवी रखे

कोरोना के वायरस ने सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का भी संकट खड़ा कर दिया है। कोरोना के कारण 421 दिन (मार्च-2020) से स्कूल बंद हैं। जिसके चलते शहर के पांच हजार स्कूल वैन चालक (परिवार के करीब 20 हजार सदस्य) आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जब से स्कूल बंद हुए हैं, रोजगार छिन गया है। दरअसल, स्कूल के बच्चों को छोड़ना और लाना ही उनका रोजगार था। अब हालात यह हो गए हैं कि घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। कोई अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा है तो कोई बीवी के गहने बेचकर खाने का जुगाड़ कर रहा है। मप्र स्कूल वाहन चालक सेवा समिति के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी का कहना है कि हमारी समिति में 4882 स्कूली वैन चालक सदस्य हैं। सरकार ने सबको राशन दिया, लेकिन वैन चालकों को नहीं। वैन चालक कर्जदार हो रहे हैं तो कई को हमने कोरोना में खो दिया। सरकार वैन चालकों के कल्याण के लिए कोई योजना जल्द लागू करे, ताकि उनका जीवन पटरी पर आ सके।

50 हजार बच्चे वैन से आते-जाते थे स्कूल

05 हजार स्कूल वैन हैं शहर में

इनकी मांगें

1. सरकार वैन चालकों के लिए रोजगार के रास्ते खोले।
2. किस्तों के लिए बैंक परेशान न करे।
3. ब्याजमुक्त लोन मिले, ताकि छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें।

राजेश नामदेव, वैन चालक

न तो रोजगार है और न ही काम का दूसरा कोई साधन

वैन ही हमारी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया थी, लेकिन कोरोना ने हमारा जीवन बुरी तरह से बदल दिया है। अब न तो हमारे पास रोजगार हैं और न रोजगार का कोई दूसरा साधन। बच्चों की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं हैं। मेरी बच्ची तो इस साल परीक्षा ही नहीं दे पाएगी।

मो. युनूस, वैन चालक

हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब तो कोई ड्राइवर भी नहीं रख रहा

मैं 17 साल से स्कूल वैन चला रहा हूं। लॉकडाउन के बाद शुरू के छह महीने तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब आमदनी ही नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ना लाजमी है। घर चलाने के लिए पत्नी के जेवर तक गिरवी रखना पड़े हैं। हालात ज्यादा बिगड़े तो एक वैन भी बेचना पड़ी। कोरोना हुआ तो इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब तो कोई ड्राइवर भी नहीं रख रहा है।

सुभाष पाटिल, वैन चालक

फीस के लिए स्कूल से रोजाना फोन आ रहे हैं

मैं ने वैन फाइनेंस करवाई थी, जैसे-तैसे किस्तें पूरी हुई तो लॉकडाउन लग गया। परिवार चलाने कुछ तो करना पड़ेगा, यह सोचकर लोडिंग ऑटो ले लिया, लेकिन काम कभी-कभार ही मिलता है। बेटियों की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूं। स्कूल से रोज कॉल आ रहा है।

जौहर कुरैशी, वैन चालक

डेढ़ साल हो गए। कहीं कोई ड्राइवर की नौकरी भी नहीं दे रहा है। फीस जमा करने के लिए स्कूल से कॉल आ रहे हैं। लॉकडाउन जब खुला था तो कुछ दिन काम मिला, लेकिन फिर सब कुछ बंद हो गया।

मो चांद, वैन चालक

बैंक वाले कह रहे हैं- किस्त जमा करो नहीं तो एफआईआर करा देंगे

मैं मेरे पास दो वैन थीं। एक बेचकर कुछ दिन काम चलाया दी। दूसरी वैन की किस्त जमा करने के पैसे नहीं हैं। बैंक वाले कह रहे हैं- किस्त जमा करो नहीं तो एफआईआर करा देंगे। यहां तो मकान का किराया, बच्चों की फीस और खाने तक के पैसे नहीं हैं। सब्जी बेचकर किसी तरह गुजर-बसर कर रहे हैं।

मो. शाहिद, वैन चालक

डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं। वैन खड़ी धूल खा रही है। पेट के लिए कुछ तो करना था, सो सब्जी का ठेला लगाने लगा। उसमें भी नुकसान हो गया। टेलरिंग का काम सीखा, लेकिन कर्फ्यू लग गया। समझ नहीं आ रहा परिवार को कैसे पालें।

भास्कर खास • वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए भोपाल के पहले शिक्षक एसपी गोस्वामी की 5 दिन पहले हुई है कोरोना से मौत

5 दिन में भी तय नहीं हुआ वे कोरोना योद्धा हैं या नहीं

ड्यूटी के प्रति इतने गंभीर कि 3 साल में सिर्फ 3 छुट्टी ली, 26 मई को बेटी की सगाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही कोरोना ने ले ली जान

अनूप दुबोलिया | भोपाल

एक ऐसा शिक्षक जिसने जिंदगी में अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत से अंजाम दिया। कोरोना काल में जहां ड्यूटी लगाई गई उसे पूरी ईमानदारी से निभाया.. लेकिन आखिर में खुद कोरोना से हार गए। उन्होंने तीन साल में सिर्फ 3 छुट्टियां ली थीं। हम बात कर रहे हैं, नवीबाग प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक एसपी गोस्वामी की। इनकी 5 दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। 6 अप्रैल को एसडीएम गोविंदपुरा ने गोस्वामी की वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी लगाई थी। इसी दौरान वे संक्रमित हुए थे। वे भोपाल जिले के पहले शिक्षक हैं जिनकी कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हुई। गोस्वामी की 4 बेटियां हैं। दूसरी बेटी नेहा की शादी 26 मई को होना थी। अयोध्या बायपास इलाके में रहने वाले एक परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। लेकिन वो इस खुशी को करीब से महसूस कर पाते, इससे पहले ही कोरोना ने 12 मई को उन्हें छीन लिया। गोस्वामी की बेटियों ने बताया कि शिक्षक होने के अलावा पापा बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। उन्होंने कभी किसी ड्यूटी के लिए इंकार नहीं किया। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे से उबर नहीं पा रहा है। बेटियां कहती हैं-पापा की कर्तव्यपरायणता और समर्पण पर गर्व है।

28 अप्रैल को हुए थे कोरोना पॉजिटिव

28 अप्रैल को बुखार आया तो गोस्वामी ने टेस्ट कराया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। निशातपुरा क्लस्टर में पदस्थ नवी बाग स्कूल की मॉनिटरिंग करने वाले जन शिक्षक उपेंद्र कौशल के मुताबिक गोस्वामी ने मेडिकल आधार पर या अर्जित अवकाश जैसी कोई लंबी छुट्टी कभी नहीं ली।

बेटी पूजा की शादी के वक्त की इस तस्वीर में पूरा गोस्वामी परिवार साथ-साथ था। शिक्षक एसपी गोस्वामी(दाएं से पहले) की चार बेटियां हैं।

कोरोना योद्धा मानें

दामाद कुणाल गोस्वामी ने बताया कि पिछले साल प्रशासन द्वारा कोरोना से निपटने के लिए लगाई गई ड्यूटी के दौरान बेहतर कार्य करने पर उन्हें कोरोना वॉरियर्स का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना कहते हैं कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान वे संक्रमित हुए हैं। तय नियमानुसार उन्हें कोरोना योद्धा मानकर समुचित मुआवजा दिया जाए। डीईओ नितिन सक्सेना का कहना है कि संकुल से प्रतिवेदन बुलवाया गया है। प्रशासन के निर्देशानुसर प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाएगा

INTERNSHIP

डिजिलॉकर प्रोजेक्ट में करें इंटर्नशिप, आवेदन 31 मई तक

डिजिलॉकर प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। डिजिलॉकर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत संचालित है। उम्मीदवारों को डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। इंटर्नशिप की अवधि 3 से 12 महीने की होगी। इंटर्न को मोबाइल डेवलपर (आईओएस) के रूप में काम करना होगा। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को टास्क दिया जाएगा जिसे उन्हें तय समय पर सबमिट करना होगा। हालांकि इसके लिए वे घर से काम कर पाएंगे। टास्क सबमिशन पर उनका ऑनलाइन रिव्यू किया जाएगा। इस इंटर्नशिप के लिए छात्रों को किसी तरह का स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इंटर्नशिप पूरी करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें वर्क स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी।

COMPETITION

आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता में जीतें डेढ़ लाख रुपए

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट (एआईसीटीएसडी) 10 जून को 'आर्य भट्ट राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता 2021' का आयोजन करेगा। इसमें भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स एआईसीटीएसडी की वेबसाइट पर 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस 290 रुपए है, जिसे छात्र डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भर सकते हैं। अंतिम परिणाम 30 जून को जारी होगा। 10 से 24 वर्ष आयु सीमा के छात्र प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता ऑनलाइन मोड में होगी। जिसमें दो अंकों के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता की अवधि 45 मिनट है। इस चरण के बाद ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू के लिए टॉप 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए छात्रों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा। इंटरव्यू के जरिए टॉप तीन छात्रों को विजेता घोषित किया जाएगा। पहले विजेता को 1.5 लाख, दूसरे को पचास हजार व तीसरे विजेता को 10 हजार की राशि दी जाएगी।

CSEET SESSION

सीएसईईटी: 27 मई से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) अपने सीएसईईटी जुलाई सेशन की शुरुआत 27 मई से कर देगा। इस दिन से नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो जाएंगी। छात्र कंपनी सेक्रेटीज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब सीएस संस्थान जल्द ही इसकी परीक्षा की तारीख भी तय कर देगा। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। सीट स्लॉट्स कम होने के कारण छात्र को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स को नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग सेशन, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सभी विषयों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग क्लासेज और 100 घंटों की कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 3500 रुपए की फीस देकर छात्र ऑनलाइन क्लासेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

वॉट्सऐप को ले डूबी पॉलिसी: सिग्नल, टेलिग्राम के यूजर्स 1200% तक बढ़े

'एनालिटिक फर्म सेंसर टॉवर' की रिपोर्ट में खुलासा, 15 मई की डेडलाइन खत्म होने से पहले एक बार फिर दोनों ऐप्स को मिला लाभ

एजेंसी ● नई दिल्ली
editor@peoplessamachar.co.in

वॉट्सऐप के प्रतिद्वंदी सिग्नल व टेलिग्राम के डाउनलोड्स में करीब 1200% की बढ़ोतरी देखी गई है। फेसबुक के मालिकाना हक वाले वॉट्सऐप ने प्राइवेसी पॉलिसी ना स्वीकारने के चलते कहा था कि यूजर्स को अपना अकाउंट डिलीट करना होगा और इसका फायदा दूसरे मैसेजिंग प्लैटफॉर्म जैसे सिग्नल व टेलिग्राम ऐप्स को मिला। ये दोनों ऐप्स ही सिक्योरिटी के मामले में बेहतर फीचर्स ऑफर करते हैं। एक रिपोर्ट में पता चला है कि टेलिग्राम व सिग्नल ने डाउनलोड्स के मामले में 1200% की बढ़ोतरी देखी गई है। वॉट्सऐप यूजर्स के लिए 15 मई को डेडलाइन खत्म होने से बिल्कुल पहले इन दोनों ऐप को एक बार फिर फायदा हुआ है। मोबाइल ऐप्लिकेशन एनालिटिक फर्म सेंसर टॉवर की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलिग्राम व सिग्नल दोनों के डाउनलोड्स में जनवरी में भारी बढ़त देखी गई। जनवरी में ही वॉट्सऐप ने अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था, जिससे फेसबुक को वॉट्सऐप यूजर्स का डाटा ऐक्सिस करने की अनुमति मिल जाएगी।

सिग्नल की ग्रोथ 1,192 प्रतिशत रही

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के पहले 4 महीनों में सिग्नल ने पिछले साल की तुलना में कुल 1,192% की ग्रोथ हासिल की। ऐप के डाउनलोड की संख्या दुनियाभर में 64.4 मिलियन हो गई। वहीं टेलिग्राम ने पिछले साल की तुलना में 98% की बढ़त की। इधर वॉट्सऐप में 43% की गिरावट देखी गई।

टेलिग्राम के 16.6 से बढ़कर 63.5 मिलियन हुए डाउनलोड

टेलिग्राम की बता करें तो पिछले साल 16.6 मिलियन की तुलना में इस साल डाउनलोड का आंकड़ा बढ़कर 63.5 मिलियन हो गया यानी कुल 283% की ग्रोथ हुई। अप्रैल में 3% की गिरावट हुई और 2020 में 27 मिलियन की तुलना में डाउनलोड्स 26.2 मिलियन रहे।

सिग्नल की ग्रोथ बरकरार

सिग्नल को जनवरी में 50.6 मिलियन बार डाउनलोड किया गया जो पिछले साल के मुकाबले 5,001% ज्यादा है। 2020 जनवरी में ऐप को कुल 9,92,000 बार डाउनलोड किया गया था। कंपनी के मुताबिक, इसके बाद कंपनी के डाउनलोड्स हर महीने कम हुए, लेकिन ऐप ने हर माह ईयर-ओवर-ईयर ग्रोथ बरकरार रखी है। 2021 में हर माह 2.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया, जबकि 2020 में यह संख्या 1.3 मिलियन थी।

नई निजता नीति को लेकर केंद्र, एफबी, वॉट्सऐप से जवाब तलब

इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक व वॉट्सऐप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार व दोनों सोशल मीडिया मंच (फेसबुक तथा व्हाट्सएप) को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

आज का इतिहास

- **1842:** महाराष्ट्र के महान विद्वान महादेव गोविंद रानाडे का जन्म।
- **1778:** जेम्स कुक ने 'हवाई द्वीपसमूह' की खोज की और इसे 'सेंडविच आइलैंड' का नाम दिया।
- **1896:** 'एक्सरे मशीन' का पहली बार प्रदर्शन किया गया।
- **1911 :** सान फ्रांसिस्को खाड़ी में खड़े जंगी जहाज पेंसिलवेनिया के उड़ान मंच पर अमेरिका के पायलट यूजीन बर्टन एली ने पहली बार विमान उतारा।
- **1930:** रवीन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की।
- **1938 :** राजनीतिक कैदियों का अंतिम जत्था अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से मुख्यभूमि के लिए रवाना हुआ।

आज का इतिहास

1933 एच डी देवगौड़ा - भारत के बारहवें प्रधानमंत्री का जन्म हुआ।

1966 पंचानन माहेश्वरी - भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी का निधन हुआ।

2012 जय गुरुदेव - प्रसिद्ध धार्मिक गुरु का निधन हुआ।

1994 संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1995 सं.रा. सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

2006 नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया।

2008 पार्श्वगायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया।

2008 भारतीय मूल के लेखक इन्द्रा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपुल हेतु कामनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया।